

, u. 50°

रांजा नं एल. डब्ल्./एन. वी. 561 लाइरोन्स नं उब्ल् वी०-41 लाइरोन्स द वोस्ट एट कन्संथनल रहे

# MANGER AND REN

## उत्तर प्रदेशीय सरकार हारा प्रकाशित

### असाधार्वा

### विधायी परिशिष्ट

भाग (4-खण्ड १(ख) (पर्तिवयत् आवेण)

लखनक, मंगलकार, 2 मई, 1989 वंगास 12, 1911 एक सम्बद्

> उत्तर प्रदेश सरकार पंचायती राज जनुभाग-1 संख्या 2866/33-1-78-83 लखनऊ, 2 मई. 1989

प0 भा0--1138

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्युक्ति नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके, राज्यणल उत्तर प्रदेश सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी (प्राविधिक) सेवा में मती और उसमें नियकत व्यक्तियों की सेवा की श्रवीं को विनिधीयत करने के लिये निम्निलिखन नियमाधनी बनाते हैं:—

उत्तर प्रदेश सहायक जिला पंचायत राज आंधकारी (प्राविधिक) संधा नियमावली, 1989

#### भाग एक-सामान्य

- 1—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश महायव किया पंचायत राज अधिकारी सीधाया नाम (प्राथिधिक) सेवा नियमावली. 1989 कही जासगी। अंद ।।।।।।
  - (2) यस त्रना प्रयुक्त होती ।

2-उत्तर प्रदेश सहायक जिला पंचायन राज अधिकारों (प्राचित्रक) संया एवं सेवा की

ale diable

3—अब मह विशेषक मा स्ट्रां हे रहें गण विस्तृत्व में हुम विशेष कार्रिके

- (क) प्रतिप्रतिक एतंपपारी का तालाई विवासन राज चित्रेशक, उत्तर प्रदेश से हैं.
- (स्व) 'भारत का नागरिक'' का गारवर्ष एसि स्ववित से हैं को संविधान है भारत-हों के अर्थीन भारत का नागरिक है या समभा वाय :
  - (ग) "आयोग" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से हैं;
  - (घ) "संविधान" का तात्पर्य "भारत का संविधान" से हैं ;
  - (ङ) "सरकार" का नात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से हैं ;
  - (च) "राज्यपाल" का तालार्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से हैं ;
- ं (७) ''सेया का सदस्य'' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पुर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौनिक रूप से निमुक्त व्यक्ति से हैं:
- (ज) "सेवा" का नात्पर्य उत्तर प्रटेश सहायक जिला पंचायत राज अधि-कारी (प्राथिषिक) सेवा से हैं ;
- (क) "मौनिक निय्वित" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर एेसी निय्वित से ही जो नदर्य निय्वित न हो और नियमों के अनुसार चयन के पद्यान की गर्या हो और पदि कोई नियम न हो तो सरकार दारा जारी किये गर्य कार्यपालक अनुदंशों द्यारा तत्समय चिहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पद्यान की गर्यों हो ;
- (त) "भर्ता का बर्व" का नान्यर्थ किसी कलेण्डर वर्ष की पहली। जुलाई से प्रारम्भ होने पानंद काल भारत की अवधित से हैं।

#### भाग दो-संगर्भ

नवा का नंधा

- 4—(1) सेवा की सहस्य मृत्या उननी होगी जिल्ली मरकार हुकरा समय-समय पर अवधारित की जास । . . .
- (2) जब तक कि उपनियम (35 के अधीन परिवर्गन करने के आहोश न दिखें जायों, सेवा की सदस्य संस्था 36 होती :

परन्त-

- (एक) निय्वित प्राथिकारी किसी रिवन पर को बिना भरों हुयें छोड़ सकता है या राज्यपान उसे आर्थ्यान राख सकते ही. जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकता न होगा : या
- (तां) राज्यपाल एसे अतिरहत स्थायां या अस्थायां पदीं या सृजन कर सकते हीं, जिन्हों वह त्रीचन समभों।

#### भाग तील-मती

भर्ती का स्रोत आरशण 5—सेवा ने पड़ों पर भनी आयोग के माध्यम से सीवी भर्ती इवारा की जायगी।
6—अनुस्चित जातियों, अनुस्चित जन-जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यदूर्ययों के लिये आरक्षण भनी के तमय प्रयुक्त सरकारी आडेशों के अनुसार किया जायगा।

#### भाग चार-अहंताएं

राष्ट्रं(यसा

7—सेवा में जिल्ही पर केंग लेकी भती के लिये यह आयद्यक हैं कि अभ्यधी —

- (क) भारत का सामांक्त हो :सा
- (स) तिकारी अस्तारी हो जो भारत भें स्थायों रूप से निवास करने के अभिग्राय से प्रत्यी अस्तर्भ, 1962 में पूर्व भारत आया हो ; या
- (स) भारतीय उद्धार कर एत्सा स्थित हो जिससे भारत में स्थामी रूप से निवास करने हैं अंश्राम कर प्रेमिक्सनान, देखाँ, श्लीवका मा किसी पूर्वी आफ्रीकी द्वीर वेग्या, उत्पादक को स्थादकों किस्तिक उत्पादकों स्थापना को विश्वीर में स्थापना को विश्वीर में स्थापना को विश्वीर में स्थापना को विश्वीर किया हो :

परन्तु उपयुचित श्रेणी (स्थ) या (ग) का अभ्यधी एरेमा व्यक्ति होना चाहिये जिसेके पक्ष में राज्य सरकार ट्यारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया नया हो :

परन्तु यह आँर कि श्रेणी (स्व) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायगी कि बह पुलिस उप महाविश्विक, गुराजर आसा, उत्तर प्रदेश धारा दिया गया पावता की प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें :

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायगा और एसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस वर्त पर रहने टिया जायगा कि वह भारत का नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी: -एसे अभ्यथीं को जिसके नामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, किन्त, न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस दार्त पर अनितम रूप से नियुक्त भी किया जा लकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके दारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

8—संवा में किसी पट पर सीधी भर्ती के लिये आवश्यक है कि अभ्यर्थी के पास शंक्षिक अहीताएं किसी मान्यता प्राप्त संस्था से यांत्रिक अभियांत्रिकी में डिप्लोमी हो ।

9—अन्य वातों के समान होने पर एंसे अध्यर्थी को सीधी भती के मामले में आधिमानी अधिमान दिया जायगा, जिसने— , अहीताएं

- (एक) प्राट्रिक सेना में ट्रां वर्ष की न्यूनतम अद्धि तक सेना की हो ; या
- (दो) राष्ट्रीय कंडोट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

10—सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की आयू भर्ती के वर्ष की पहली जुलाई को आयू 21 वर्ष की हो जानी चाहिये और 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये :

परन्तु अनुस्चित जातियाँ, अनुस्चित जन-जातियाँ और एंसी अन्य श्रेणियाँ के. जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिस्चित की जायं, अभ्यधियाँ की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

11—सेवा में किसी पट पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चरित्र चाहिये कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी: —संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पट पर नियुचित के लिये पात्र नहीं होंगे। किसी एसे अपराध के लिये जिगमें नैतिक अवसता अन्तर्यंतित हो, दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

12—सेवा में किसी पट पर नियाकत के लिये ऐसा पुरुष अभ्यर्था पात्र न होगा वैवाहिक प्रास्थिति जिसकी एक से अधिक प्रतिनयां जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से ब्रिकाह किया हो जिसकी पहले से कोई पत्नी जीवित हो :

परन्त, राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से पृट दें सकते हैं यदि उनका यह समाधान हो जाय कि एता करने के लिये विशेष कारण विद्यमान हैं।

13—िकसी भी अभ्यर्थी को छेवा में किसी पद पर तभी नियुक्त किया जायना द्वारीस्क जब मानसिक और दार्सारक कष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और यह ऐसे सभी स्वस्थता द्वारीरिक होप से मुक्त हो जिससे उसे अपने कर्जध्यों का हथनापूर्वक पानन करने में

किसी अभ्यर्थी को निस्तित के लिये अन्तिय हुए से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायसी कि वह फण्डामेन्ट्रज रूज 10 के अधीन पनाये नये और फोड्रचेन्द्रियल हैंण्ड कुक स्वण्ड—हों. भाग तीन के अध्याय तीन में दिये नये नियमों के अनुसार सबस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तृत करों।

#### भाग-पांच-भर्ता की प्रक्रिया

रियतयो का अववारण 14-निय्वित प्राधिकारी वर्ष के द्वारान भरी जाने वाली सिक्तयों की संख्या अंत नियम संख्या 6 के अधीन अनुस्चित जातियों अनुस्चित जन-जातियों और अन्य धीणयों के अभ्यथियों के लिये आरक्षित की जाने वाली सिवतमों की संख्या भी अब-धीरत करोगा और उसकी सुचना आयोग को दोना।

सीधी भती की प्रक्रिया 15—(1) चयन के लिये विचारार्थ आवेदन-पत्र आयोग द्वारा विहित प्रपत्र में आमित्रत किये जायेंगे, जो भुगतान किये जाने पर, यदि कोई हो, आयोग के सचिव से प्राप्त किये जा सकते हैं।

F

3

15

37

Fe

3

3

- (2) आयोग नियम 6 के अनुसार अनुस्चित जातियों, अनुस्चित जन-जातियां और अन्य श्रीणियों के अम्पर्थियों का सम्यक् प्रतिनिधित्य सुनिश्चित करने की आव-श्यकता को ध्यान में रखते हुये साक्षात्कार के लिये उतने अभ्यर्थियों को, जो अपेक्षित अर्थताएं पूर्व करते हों, बुलायेगा जितने वह उचित सममें।
- (3) आयोग अभ्यर्थियों की उनकी प्रकीणता क्रम में, जैसा कि साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को प्राप्त अंकों से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा। यटि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें तो आयोग उनके नाम सेवा के लिये उनकी सामान्य उपगुक्तता के आधार पर योग्यता-क्रम में रखेगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु पच्चीस प्रतिदात से ज्याटा अधिक नहीं) होती। आयोग नियुक्ति प्राधिकारी को सूची अग्रसारित करेगा।

#### भाग-छ:-नियुक्ति, परिश्रीक्षा, ज्येष्टता और स्थायीकरण

नियुक्ति

- 16-(1) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यधियों की नियुक्तियां उसी कम में करोगा जिसमें उनके नाम नियम 15(3) के अधीन तैयार की गयी सुची में हों।
- (2) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुचित के एक से अधिक आदेश जारी किये जाये तो एक संयुक्त आदेश. भी जारी किया जायगा जिसमें व्यक्तियों के नाम का उल्लंख चयन में यथा-अवद्यारित व्यव्यक्ता-क्रम में किया जायगा।
- (3) नियुक्ति प्राधिकारी अस्वायां या रेधानापन्त के सब में भी उपनियम (1) में निर्विष्ट सुनी से नियुक्तियां कर सकता है! यदि इस मुनी का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो वह ऐसी रिक्तियां में इस नियमावली के अधीन नियुक्ति के लिये एक व्यक्तियों में से नियुक्तियां कर सकता है! ऐसी नियुक्तियां एक वर्ष की अबधि या इस नियमावली के अधीन अवला चयन किये जाने तक, इनमें जो भी पहले हो, से अधिक नहीं चलेगी और यटि पट आयोग के संवान्तगंत हो तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम, 1954 के विनियम 5(क) के उपजन्ध लागू होंगे।

परिनीक्षा

- 17—(1) सेवा में किसी पट पर. तथायी सिंवत में या उसके प्रति नियुक्ति किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायगा।
- (2) नियाकित प्राधिकारी एसे कारणों से जो अमिलिखित किये जाये, अलग-अलग मामलों में परिशिक्षा अर्थाध बट्टा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया आयगा जब तक अर्थाध बट्टायी जाय:

परन्त, आपबादिक परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा-अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो गर्प से अधिक नहीं महायी जायगी।

- (3) यह परियोक्षा अयोध या यहायी गयी परियोक्षा अवधि के टौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियानित प्राधिकारों को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विकल रहा है तो उसके मौतिक पट पर यहि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यहि उसका किसी पट पर धारणाधिकोंद्र न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।
- (4) उप नियम (3) के अधीन जिस परिवीक्षाधीन व्यक्ति को प्रयावर्ति किया जाम या जिसकी सेवामें समाप्त की जायें. यह किसी प्रतिकर का हफदार नहीं होंगा।

स्थाधीकरण

- 18-किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बटायी गयी परिवीक्षा-अवधि के अस्त में उसकी नियक्ति में स्थायी कर टिया वायसा —यांट
  - (फ) उसका कार्य और आचरण संतांषजनण बनाया जाय :
  - (ख) उसकी मन्यनिष्टा प्रमाणित का ही जाब ; और

- (ग) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायी किये जाने के लिये अन्यथा उपस्कत है।
- 19-(1) किसी अभ्यार्थी की ज्येष्टता मौतिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से ज्येष्टता और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जायं तो उस कम से जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गये हों, अवधारित की जायेगी :

परन्तु यदि नियाकित के आदेश में किसी व्यक्ति की मांलिक नियाकित का कोई विधिष्ट पूर्ववती दिनांक निर्दिष्ट किया जाय तो उस दिनांक को मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनांक समभा जायगा और अन्य मामलों में, उसका तात्पर्य आदेश जारी किये जाने के दिनांक से होगा:

परन्तु यह और कि यदि किसी एक चयन के संबंध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जाये तो ज्येष्ठता यही होगी जो नियम 16 के उपनियम (2) के अधीन जारी किये गये नियुक्ति के संयुक्त आरोश में उन्मिस्ति हों।

(2) किसी एक चयन के परिणाम के आधार पर सीधे, नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वहीं होगी जो चयन के समय आयोग हवारा अवधारित की गयी हो :

परन्तु सीधे भती किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है यदि किसी रिकित का प्रस्ताव किये जाने पर वह युक्तियुक्त कारणों के विना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहे। कारण की युक्तियुक्तता के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा।

#### भाग-सात येतन इत्यादि

- 20-(1) सेवा में किसी पढ पर, चाहें मौलिक वा स्थानापनन रूप में हो या वेतन अस्थायी आधार पर, नियुक्त व्यक्ति का अनुमन्य येतनमान एसा होगा जैसा सरकार व्यारा समय-समय पर अवधारित किया जाय !
- (2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय सेवा में पदों का वेतनमान 515-15-590-18-626-20 + 170-18-680-20 770-20-780-20 20-860 रुपये हैं।
- 21-(1) फण्डामेन्टल रूला में किसी प्रतिकृत उपबन्ध के हांते हुसे भी, परि- परिवीक्षा-अवधि पीक्षाधीन स्पित को, यति यह पहले से स्थापी सरकार सेवा में न हो, समयमान में में मेतन प्रथम येतन गृद्धि तभी दी जायंगी जय उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा प्री कर ली हों. और दिलीय वेतनवृद्धि हो वर्ष की सेवा के पश्चान तभी ही जायगी बब उसने परिशिक्षा-अरवधि पुरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया नया हो :

परन्तु यदि संतोण प्रदान, न कर सकने के कारण परिनीक्षा-अवधि बढ़ायी जाय तो इस. प्रकार बढ़ायी गयी अवधि गणना बेतनबृद्धि के लिये नहीं की जायगी। जब तक कि निय्वित प्राधिकारी अन्यथा निटंश न है।

(2) एसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद घारण कर रहा हो, परिवीक्षा-अवधि में बीतन स्तंगत फण्डामेन्टल रून्स हारा विनियमित होगा :

परन्तू यदि संतोप प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा-अवधि गटायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन-गृद्धि के निये नहीं की जायगी । जह तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निटंश न है। है

(3) एसे व्यक्ति का जो पहले से स्थापी सरकारी सेवा में हो, प्रसिक्षा-अवस्थि में वैतान राज्यकानाम के सम्बन्ध में सेवास्त्र सरकार्य सेवको एर सामान्यस्या लाग् ससंसत नियमो हारा विनियमित होगा।

#### 22-किमी व्यक्ति को-

दक्षतारोक पार (एक) प्रथम उक्षनासांक पार करने फी अस्पति तब तक मधीं टी आयर्गी वाने का मान-जय तथा कि उसने अपने कार्य का पर्याप्त झान अजिंत न्या हो। और पर्याप्त दाँरा और निरिष्टण कार्य और समय-समय पर जारी किये नथे निर्देशों के असमार राजि अवस्था र किया हो प्रसाम कार्य और व्यक्तम संसोध स्था स

(दो) दितीय और तृतीय दक्षतारोक वार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायगी जन तक कि यह न पाया जाय कि उसने धीरतया अपनी सम्पूर्ण योग्यता से कार्य किया है और वह कार्यालय और पंचायत उत्तोग कर ध्रवन्य करने में समर्थ हैं, उसका अपने अधीनस्था पर अच्छा नियंत्रण हैं और उसका कार्य और आंचरण संतोधजनक हैं और जर्भ तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर-दी जाय।

पत्र समर्थन

23—सेवा में पर्दा पर लागू नियमों के अधीन अपिक्षत तिकारिय से भिन्न किसी भी सिकारिय पर, चाहे वह लिखित हो या मांखिक विचार नहीं किया जायगा। किसी अभ्यथीं की ओर से अपनी अभ्यधिता के लिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियक्ति के लिसे अनुह कर देंगा।

णन्य विषयो का विनियमन 24—एंसे विषयों के संबंध में जो विश्लेष रूप से इस न्यमाणली था विद्रीष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों हारा नियंत्रित होंगे।

सेवा की छत्तों<sup>द</sup> में शिथलता

1 - 1 - 1 - 94.

.. 25—जहां सरकार का यह समाधान हो जाय कि लेगा में नियम के प्रवृत्त व्यक्तियों की लेगा की शतों को बिनिग्रमित करने वाले किसी नियम के प्रवृत्ति से किसी विद्याप्त मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहां वह, उस-मामले में लाग नियमों में किसी बात के होते हमें भी. आदेश दारा. उस सीमा तक और ऐसी शतों के अधीन रहते हमें, जिन्हों वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण शिति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समभे, उस नियम की अपेक्षाओं से अभिमृक्ति दे सकती हैं और या उसे शिवल कर सकती हैं:

परन्त, जहां कोई नियम आयोग के परामर्थ से बनाया गया हो, वहां उस नियम की अपेक्षाओं से अभिम्बित टेने या उसे शिथित करने के पूर्व आयोग से परामर्श किया जायगा।

ब्यावृत्ति

26—इस नियमावानी में किसी बात की कोई ग्रमीय एसे आरक्षण और अन्य रियायती पर नहीं पड़ेगा जिसका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और व्यक्तियों की अन्य विशेष श्रीणयों के अम्यार्थियों के लिये उपवन्ध किया जाना अमेशित हो।

डा0'इन्द्रं प्रकाश एरेनः

(1) Th

(Tecl

nost.

-M.SC

ject

50

10'

n

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 2866/XXXIII-1—78-83, dated May 2, 1989:

No. 2866/XXXIII-1-78-83

Dated Lucknow, May 2, 1989

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of the existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules regarding recruitment and the conditions of service of persons appointed to the Uttar Pradesh Assistant District Panchayat Raj Officer (Technical) Service.

THE UTTAR PRADESH ASSISTANT DISTRICT PANCHAYAT RAJ OFFICERS (TECHNICAL) SERVICES RULES, 1989

PART-1-GENERAL

Short title and 1. (1) These roles may be called the Uttar Pradesh Assistant

n! 720 The Uttar Pradesh Assistant District Panchayat Raj Officers ((Technical) Service is a non-gazetted service comprising, group Grant Fotor; in each office algebra matter to normal 2 (2)

Status of Service

ject or context, and the sub-

Definitions

- (a) "Appointing Authority" means the Director of Panchayati
  Raj Uttar Pradesh;
  - (b) "Citizen of India" means a person who is or is deemed to be a citizen of India Part—II of the Constitution;
  - (c) "Commission" means the Uttar Pradesh Public Service Commission;
    - (d) "Constitution" means the Constitution of India; "
  - (e) "Government" means the State Government of Uttar Pradesh;
  - "(f) "Governor" means the Governor of Uttar Pradesh";
- (g) Member of Services means a persons appointed in a substantive capacity under these rules or the rules or orders in froce prior to the commencement of these rules, to a post in the cadre
  - " (h) "Service" means the Uttar Pradesh Assistant District Panchayat Raj Officers (Technical) Service
  - (i) "Substantive appointment" means an appointment not being an ad hoc appointment, on a post in the cadre of the service, and after selection in accordance with the rules and, if there are no rules, in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instructions issued by the Government;
  - (j) "Year of recruitment" means period of 12 months commencing from the first day of July of a Calendar year.

4. (1) The strength of the service shall be such as may be determined by the Government from time to time.

Cadre of Service

\*. (2) The strength of the service shall, until orders varying the same are passed under such rule (1) be 56:

...Provided that-

- Governor may held in abeyance any vacant post without thereby entitling any person to compensation, or
  - .(ii) The Governor may create such additional permament or temporary posts as he may consider proper.

### PART III—RECAUITMENT

through the Commission.

6. Reservation for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories shall be in accordance with the orders of the Government in force at the time of the recruitment.

Reservation

#### PART IV-QUALITICATIONS

7. A candidate for direct recruitment to a posts in the comis-

- (b) a Tibetan refugee who came over to India before the Ist January, 1962 with the intention of permanently settling in India, or
- (c) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or any of the East African countries of Kenya, Uganda and the United republic of Tanzania (formerly Tanganika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India:

Provided that a candidate belonging to category (b) or (c) above must be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the State Government:

Provided further that a candidate belonging to category (b) will also be required to obtain a certificate of eligibility granted by the Deputy Inspector General of Police, Intelligence Branch Uttar Pradesh:

-3

F

54

ij

n .

al

3

(

Provided also that if a candidate belongs to category (c) above, no certificate of eligibility will be issued for a period of more than one year and the retention of such a candidate in service beyond the period of one year, shall be subject to his acquiring Indian Citizenship.

Nore—A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refused may be admitted to an examination or interview and he may also be provisionally appointed subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his favour.

Academic Oualifications 8. A candidate for direct recruitment to the post in the service must possess a Diploma in Mechanical Engineering from any recognized institution.

Preferential Qualifications

- 9. A candidate who has -
  - (i) Served in the Territorial Army for a minimum period of 2 years; or
  - (ii) Obtained a 'B' certificate of National Cadet Corps, shall, other things being equal, be given preference in the matter of direct recruitment.

Age

10. A candidate for a direct recruitment must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of more than 30 yeras on July 1 of the year of recruitment:

Provided that the Upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other categories as may be notified by the Government from time to time, shall be greater by such number of years as may be specified.

Character

11. The character of a candidate for direct recruitment to a post in the service must be such as to render him suitable in all respect for employment in Government service. The appointing authority shall satisfy itself on this point.

Note-Persons dismissed by the Union Government or a State Government or a Local Authority or by a Corporation or Body owned or controlled by the Union Government or a State Government shall be ineligible for appointment to

12. A male candidate who has more than one wife living or a female candidate who has married a man already having a wife living shall not be eligible for appointment to a post in the service :

Marital Status

Provided that the Governor may if satisfied there exist special grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

Physical Fitness

13. No candidates shall be appointed to a post in the service unless he be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties. Before a candidate is finally approved for appointment; he shall be required to produce a medical certificate of fitness in accordance with the rules framed under fundamental rule 10 and contained in chapter III of the Financial Handbook Vol. II, Part III.

#### PART V -- PROCEDURE FOR RECRUIMENT

14. The appointing authority shall determine and intimate to the Commission, the number of vacancies to be filled during the course of the year at also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories under rule 6.

Determination of vacancies

15. (1) Application for being considered for selection shall be called by the Commission in the prescribed form, which may be obtained Direct Recruitfrom the Secretary to the Commission on payment, if any.

Procedure fer

- (2) The Commission shall, having regard to the need for scenning representation of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories in accordance with rule 6, call for interview such number of candidatès who fulfil the requisite qualification, as they consider proper.
- (3) The Commission shall prepare a list of candidates in order of their proficiency as disclosed by the marks obtained by each candidate in the interview. If two or more candidates obtain equal marks, the Commission shall arrange their names in order of merit on the basis their general suitability for the service. The number of the names in the list shall be larger (but not larger by more than 25%) than the number of the vacancies. The Commission shall forward the list to the appointing authority.

PART VI-APPOINTMENT, PROBATION, SENIORITY AND CONFIRMATION

16. (1) The appointing authority shall make appointment by taking the names of candidates in the order in which they stand in the list prepraed under rule 15(3).

Appointmea 1

- (2) If more than one orders of appointments are issued in respect of any one selection, combined list shall also be issued mentioning of the name of the person in order of seniority as determined in the selection.
- (3) The appointing authority may make appointments in temporary or officiating capacity also from the list referred to in sub-rule (1). If no candidate borne in the list is available he may make appointment in such vacancies from amongst persons eligible for appointment under these rules. Such appointments shall not last for a period exceeding one year or beyond the next selection under these rules whichever be carlier, and where the post is within the purview of the commission, the previsions of regulation 5(n) of the Uttar Pradesh Public Service Commission (Limitation of Functions) Regulations, 1951 shall apply.

Probation

- 17. (1) A person on appointment to a part in the service in or ognisat a parameter vacancy shall be pinced on probation for period of "no very».
- (2) The appointing anthority may, for receives to be recorded; extend the period or probation in individual cases specifying the date upto which the extention is granted:

710

151

377

11

m

I2

111

G

gi af

8

Provided that save in exceptional circumstances, the period of probation shall not be extended beyond one year and in no circumstances beyond two years.

- (3) if it appears to the appointing authority at any time during or at the end of period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, he may be reverted to his substantive post if any, and if he does not hold a lien on any post his services may be dispensed with.
- (4) A probation who is reverted or whose services are dispensed with under sub-rule (3) shall be entitled to any compensation.

Confirmation

- 18. A probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or the extended period of probation if,—
  - (a) his work and conduct are reported to be satisfactory :
  - (b) his integrity is satisfied; and
  - (c) the appointing authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmation.

Seniority

Pay

19. (1) Seniority of a candidate shall be determined from the date of the order if substantive appointment and if two or more persons are appointed together, from the ender in which their names parameters and in the appointment order:

Provided that if the appointment order specifies a particular back date with effect from which a person is substantively appointed that date will be deemed to be the date of order of substantive appointment and in other cases it will mean the date of issuing the order:

ned in the combined the order of appointment issued under sub-rule (2) of rule 16.

(2) The seniority inter-se of persons appointed directly on the result of any one selection shall be the same as determined at the time of selection by the commission:

Provided that candidate recruited directly may lose his seniority if he fails to join without vaild reasons when a vacancy is offered to him. The decision of the appointing authority as to the validity of the reasons shall be final.

#### PART VII-PAY PTC

20. (1) The scale of pay admissible to persons appointed to a post in the service; whether in a substantive or officiating capacity or as temporary measure, shall be such as may be determined by the Government from time to time.

72) The scale of Pay of the peets in Vervice of the time of the consequence and of these rules in Plances 515-15-590-18-626 - EB-scale and series 20 - 750-16B - 20 - 500.

21. (1) Nothwithstanding any provision in the fundamental rule to the contrary, a person on probation, if he is not already in permanent Government service shall be allowed first increment in the time scale when he has completed one year of satisfactory service, and second increment after 2 years service when he has completed the probationary period and is also confirmed:

Probation -

Provided that if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction such extention shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

(2) The pay during probation of a person who was already holding a pool under the Government shall be regulated by the relegant fundamental rules:

Provided that if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction such extention shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

(3) The pay during probation of a normal above in recomment

generally to Government servants serving in connection of with the affairs of the State.

22. No person shall be allowed to cross-

Criteria for crossing efficiency bars

- (1) The first effeciency Bar unless he is found to have acquired sufficient knowledge—of his work and has done sufficient touring and inspection work and made night halts according to the instructions issued from time to time, his work and conduct are found to be satisfactory and unless his integrity is certified;
- (2) The second and the third effeciency Bars unless he is found to have worked steadily to the best of his ability and capable of managing the office and the Panchayat Udyogs, has a good control over his subordinates and his work and conduct are found to be satisfactory and unless his integrity is certified.

#### PART VIII-OTHER PROVISIONS

23. No recommendations, either written or oral other than those required under the rules applicable to the post in the service will be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support, directly or indirectly for his candidature will disqualify him for appointment.

Convassing

24. In regard to the matters not specially covered by these or by special order, persons appointed to the service shall be Governed by the rules, regulations and orders applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the state.

Regulation of other matters

25. Where the Government is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of service of persons appointed to the service causes undue hardship in any particular case, it may, notwith-standing anything contained in the rules applicable to the case, by order, dispense with or relax the requirement of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner:

Relaxation in the condition of Service

Provided that when a rule has been made in consultation with the commission, that body shall be consulted before the requirements of the rule are dispensed with or relaxed.

Saving

26. Nothing in these rules shall rifect reservation and other concession required to be provided for the candidate belonging to the scheduled castes, scheduled tribes and other specified categories of persons in accordance with the order of the Government issued from time to time in this regard.

Dy order,
Dr. I. P. ARON,
Suchin



रिजि नि एलि डब्ल् ०/एन० पी 561 लाइसेन्स नं 0 डब्ल् पी 0 /41 लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रटे

# सरकारी गजह, उत्तर अदेश

### उत्तर प्रदेशीय सरकार हारा प्रकाशित

### असाधारगा

### विवायी परिशिष्ट

भाग-- 4, खण्ड (ख) ( परिनियत ग्रादेश)

लखनऊ, शनिवार, 18 नवस्बर, 1989 कार्तिक 27, 1911 शक सम्वत

#### उत्तर प्रदेश सरकार

पंचायती राज अनुभाग-1

संख्या 6022/33-1-68-77 लखनऊ, 18 नवम्बर, 1989

#### अधिस् चना प्रकीर्ण

प0 ग्रा0--1575

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश सहायक विकास अधिकारी (पंचायत एवं समाज शिक्षा) सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:--

उत्तर प्रदेश सहायक विकास अधिकारी (पंचायत एवं समाज शिक्षा) सेवा नियमावली 1989

#### भाग एक-सामान्य

1--(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सहायक विकास ग्रांधकारी (पंचायत एवं समाज संक्षिप्त नाम शिक्षा) सेवा नियसावली, 1989 कही जायगी। - শ্লীং সাংস্থ

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थित 2- - उत्तर प्रदेश सहायक विकास ग्रविकारी (पंचायत एवं समाज शिक्षा) सेवा एक ग्रराजी पत्नित सेवा है जिसमें समृह "ग" के पद सम्मिलित हैं।

परिभाषाएं

- 3-- जब तक कि विषय या सदर्भ में कोई बात प्रतिकृत न हो, इस नियावली में---
  - (क) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य यथास्थिति संयुक्त निदेशक या उप निदेशक (प्रशासन) से है जो तत्समय प्रशासन का कार्य देख रहे हों;
  - (ख) "भारत का नागरिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग दो के ब्रधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय ;
    - (ग) "श्रायोग" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा श्रायोग से है ;
    - (घ) "संविधान का तात्पर्य" भारत का संविधान से है ;
    - (इ) "सरकार" का तात्पर्यं उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है ;
    - (चं) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;
  - (छ) "सेवा का सदस्य" का तात्पर्य सेवा के सम्वर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या ग्रादेशों के ग्रधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है;
  - (ज) "सेवा" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सहायक विकास अधिकारी (पंचायत एवं समाज शिक्षा) सेवा से है;
  - (झ) "मौलिक नियुक्ति का तात्पर्य" सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से हैं जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो ;
  - (ञा) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की ग्रवीध से है।

#### भाग दो-संवर्ग

सेवा का संवर्ग

- 4——(1) सेवा की सदस्य संख्या ऐसी होगी जिसे राज्यपाल द्वारा समय-समय पर प्रवधा-रित्त किया जाय।
- (2) जब तक कि उपनियम (1) के अधीन उसमें परिवर्तन करने के आदेश न दिये जांय सेवा की सदस्य संख्या 944 होगी:

परन्तु--

- (एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सफते हैं या राज्य-पाल उसे ग्रास्थिगित रख सकते हैं जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा ;
- (दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं जिन्हें वह उचित समझें।

#### भाग तोन-भर्ती

भर्ती का स्रोत

- 5--सेवा में भर्ती, यथा सम्भव, निम्नलिखित स्नोतों से की जायगी--
  - (एक) कुल रिक्तियों का पचास प्रतिशत ग्राम पंचायत श्रधिकारियों में से पदोन्नित द्वारा ;
    - (दो) पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।

श्रारक्षण

6--अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यिथों के लिये धारक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार किया जायगा।

#### भाग चार-ग्रर्हतायें

राष्ट्रीयता

7--सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह खावश्यक है कि अभ्यर्थी--

- (क) भारत का नागरिक हो, या
- (ख) तिब्बती शरणार्पी हो जो भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्रान् से 1 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अभीकी देश केनिया, उगाण्डा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तंजानियां (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो :

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पालता का प्रमाण-पत्न जारी किया गया हो ;

परन्तु यह श्रौर कि श्रेणी (ख) के श्रभ्यर्थी से यह भी श्रपेक्षा की जायगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, गुष्तचर शाखा, उत्तर प्रदेश से पावता का प्रमाण-पव प्राप्त कर लें:

परन्तु यह भी कि यदि कोई ग्रम्पर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पावता का प्रमाण पत्न एक वर्ष से अधिक अविधि के लिये जारी नहीं किया जायगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में तभी रखा जा सकेगा जबकि उसने भारतीय नागरिकता

टिप्पणी--ऐसे अभ्यर्था का जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इंकार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सिम्मिलित किया जा सकेगा श्रीर उसे इस शर्त पर अनिन्तम रूप से नियुक्त भी किया जा सकेगा कि आवश्यक प्रमाण-पद उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

8--सेया में सीबी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी के पास भारत में विधि द्वारा शिक्षिक अर्हताएं स्यापित किसी निरतिबद्यात्रम को कर से करें स्तालक उपाधि हो।

• 9-- ग्रन्य बातों के सनान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे ग्रभ्यर्थी को अधिमान दिया ग्रधिमानी ग्रहंता जायगा, जिसने ---

- (1) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो ;
- (2) राष्ट्रीय कैंडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्न प्राप्त किया हो ।

10--सीधी सर्ती के लिये ग्रम्थर्थी की ग्रायु भर्ती के वर्ष की पहली जुलाई को 21 वर्ष की हो साय जानी चाहिए और 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए:

परन्तु स्तृगूचित जात्वेयों, स्रनुसूचित जनजातियों स्रौर ऐसी सन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जांय, अध्यथियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष ग्रधिक होगी जितनी विनिदिष्ट की जाय।

11-सेवा में सीबी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये कि वह सरकारी सेवा में नियोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में प्रपना समाधान कर लेगा।

चरित्र

टिज्पणी:--संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वानित्व में या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पान नहीं होंगें। किसी ऐसे अपराध के लिये जिसमें नैतिक अद्यमता अन्तर्वलित हो. दोषसिद्ध व्यक्ति भी पान नहीं होंगे।

12--सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पाल न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो या ऐसी महिला अभ्यर्थी पान न होगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो :

वैवाहिक प्रास्थिति

शारीरिक

स्वस्थता

परन्तु राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं, यदि उनका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण विद्यमान हैं।

13--किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायगा जब तक कि मानसिक ग्रौर शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य ग्रच्छा न हो ग्रौर वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिस है उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो । किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायगी कि वह फण्डामेन्टल रूल 10 के अधीन बनायें गये और फाइनें शियल हैण्ड बुक, खण्ड दो, भाग तीन, के अव्याय तीन में दिये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण-पत्न अस्तुत करें :

परन्तु पदोन्नति द्वारा नर्ती किये गये ग्रम्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण-पत्न की श्रपेक्षा नहीं की जायगी !

### भाग पांच-भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों का अवधारण

14--नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यांवयों के लिये आर-क्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी स्रवधारित करेगा और उसकी सूचना स्रायोग को देगा।

सीघी भर्ती की प्रक्रिया

- 15--(1) सेवा में सीघी भर्ती स्रायोग के माध्यम से प्रतियोगिता परीक्षा के स्राधार पर
- (2) प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमित के लिये आवेदन-पद्म ग्रायोग की जायगी। से, उनके द्वारा विज्ञापित रूप विधान में म्रामंत्रित किये जायेंगे।
- (3) किसी ग्रभ्यर्थों को परीक्षा में तब तक सम्मिलित नहीं किया जायगा जब तक कि उसके ामाश्रायोग द्वारा दिया गया प्रवेश प्रमाण-पत्न न हो ।
- (4) आयोग लिखित परीक्षा का परिणाम प्रान्त होने और रारणी वढ कर लिये जाने के पश्चात्, नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य अभ्यथियों का सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की भ्रावश्यकता को ध्यान में रखते हुए, उतनी संख्या में ग्रभ्याथयों को साक्षात्कार के लिये बुलायेगा जितने इस सम्बन्ध में लिखित परीक्षा के परिणाम के ग्राधार पर भ्रायोग द्वारा निर्धारित स्तर तक पहुंच सके हो। लिखित परीक्षा में उसके द्वारा प्राप्त किये गये भ्रंकों में जोड़ दिये जायेंगे।
  - (5) आधार अभ्यथियों की योग्यता क्रम मं, जैसा कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में उनके द्वारा प्राप्त अंकों के कुल योग से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा और उतनी संख्या में ग्रभ्यथियों की सिफारिश करेगा जितने वह नियुक्ति के लिये उचित समझे । यदि दो या ग्रिधिक ग्रस्थर्थी बराबर-बराबर कुल ग्रंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में ग्रपेक्षाकृत ग्रधिक ग्रंक प्राप्त करने वाले ग्रभ्यर्थी का नाम उच्चतर स्थान पर रखा जायगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से ग्रिधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से ज्यादा ग्रिधिक नहीं) होती। ग्रायोग सूची नियुक्ति प्राधिकारी दो अप्रसारित कर देशा।

टिप्पणी--सेवा में पदों पर सीधी भर्ती संयुक्त ग्रवर ग्रधीनस्थ सेवा परीक्षा (स्नातक समूह) के परिणाम पर की जायगी।

पदोन्निति हार्ग भर्ती की प्रक्रिया

16-- पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियम वली, 1970 के अनुसार की जायगी।

संयुक्त स्ची

17---यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों ही प्रकार से की जानी हों तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायगी जिसमें अभ्यिथयों के नाम बारी-बारी से सुसंगत सूचियों से लिये जायेंगे । सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।

### भाग छ:-नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायोकरण ग्रौर ज्येष्ट्रता

नियुक्ति

- 18--(1) उप नियम (2) के उपबन्धों के ग्रधीन रहते हुए, नियुक्ति प्राधिकारी ग्रभ्यथियों की नियुक्तियां उसी कम में करेगा जिसमें उनके नाम, यथास्थिति, नियम 15, 16 या 17 के प्रधीन
- (2) जहां, भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती ग्रौर पदोन्नित दोनों प्रकार से तैयार की गयी सूचियों में हो। की जानी हों, वहां नियमित नियुक्तियां तब तक नहीं की जायंगी जब तक दोनों स्रोतों से चयन न कर लिया जाय और नियम 17 के अनुसार एक संयुक्त सूची तैयार न कर ली जाय।
- (3) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में एक से ग्रिधिक नियुक्ति के ग्रादेश जारी कि जायं तो एक संयुक्त ग्रादेश भी जारी किया जायगा जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख, यथास्थिति चयन में यथा ग्रवधारित या उस संवर्ग में जिससे उन्हें पदोन्नति किया जाय, विद्यमान ज्येष्ठता त्र में किया जायगा। यदि नियुक्तियां सीधी भर्ती ग्रौर पदोन्निति दोनों प्रकार से की जायं तो न
- नियम 17 में निदिष्ट चन्नानुन्नम में रखे जायेंगे । (4) नियुक्ति प्राधिकारी ग्रस्थायी या स्थानापन्न रूप में भी उप नियम (1) में निवि सूची से नियुक्तियां कर सकता है। यदि इन सूचियों का कोई ग्रम्यर्थी उपलब्ध न हो तो वह ए रिक्तियों में इस नियमावली के अधीर नियुक्ति के लिये पात व्यक्तियों में से नियुक्तियां कर सब है। ऐसी नियुक्तियां एक वर्ष की अवधि या इस नियमावली के अधीन अगला चयन किये र तक, इनमं जो भी पहले हो, से अधिक नहीं चलेंगी और जहां पद आयाग के क्षेत्रान्तरगत हो, उत्तर प्रदश लोक सेवा आयोग (हृत्यों का परिसीमन) विनियम, 1954 के विनियम 5(क) के बन्ध लाग् होंगे।

19---(1) से बामें कि शिपद पर स्वाबा रिक्ति में या उस के ब्रोत नियुक्ति किये जाने पर अत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायगा।

परिवीक्षा

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग-अलग मामलों में परिलीक्षा अविध को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायगा जब तक अविध बढ़ायी जाय:

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा अविध एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो दर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायगी।

- (3) यदि परिवीक्षा ग्रविध या बढ़ायी गयी परिवीक्षा ग्रविध के दौरान किसी भी समय या उसके ग्रन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने ग्रपने ग्रवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या संतोष प्रदान करने में ग्रन्थथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावीतित किया जा सकता है ग्रौर यदि उसका किसी पद पर धारणा-िध र न हो तो उसकी सेवाय समाप्त की जा सकती है।
- (4) उप नियम (3) के अधीन जिस परिवीक्षाधीन व्यक्ति को प्रत्यावितित किया जाय का जिसकी सेवायें समाप्त की जाय, वह किसी प्रतिकर का हकदार न होगा।
- (5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी ग्रन्य समकक्ष या उच्चतर पट पर स्थानापन या ग्रस्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा ग्रवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की ग्रनुमति दे सकता है।

32 — किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अविध या बढ़ारी गयी परिवीक्षा अविध के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायगा, यदि—

स्थायीकरण

- (क) उसने विहित विभागीय परीक्षा, यदि कोई हो, उत्तीर्ण कर ली हो ;
- (ख) उसने विहित प्रशिक्षण, यदि कोई हो, सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो ;
- (ग) उसका कार्य और भाचरण संतोषजनक बताया गया हो ;
  - (घ) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी गयी हो ; ग्रौर
- (ङ) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायीकरण के लिये अन्यथा उपयुक्त है।

21--(1) एतद्पश्चात् यथा उपबन्धित के सिवाय, ज्येष्ठता मौलिक नियुक्ति के थादेश के दिनाक से और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जाय तो उस कम में, जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गये हों, अवधारित की जायगी:

ज्<u>ये</u>ष्ठता

परन्तु यदि नियुक्ति के आदेश में किसी व्यक्ति की मौलिक नियुक्ति का कोई विशिष्ट पूर्ववर्ती दिनांक विनिदिष्ट किया जाय तो उस दिनांक को मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनांक समझा जायगा और अन्य मामलों में उसका तात्पर्य आदेश जारी किये जाने के दिनांक से होगा :

परन्तु यह और कि यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्ति के आदेश जारी किये जायं तो ज्येष्ठता वही होगी जो नियम 18 के उप-नियम (3) के अधीन जारी किये गये नियुक्ति के संयुक्त आदेश में उल्लिखित हो।

(2) किसी एक चयन के परिणाम के आधार पर सीधे नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो आयोग द्वारा अवधारित की गयी हो;

परन्तु सीधी भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है, यदि किसी रिक्त पद का प्रस्ताव किये जाने पर वह युक्तियुक्त कारणों के बिना कार्य-भार ग्रहण करने में विफल रहे। कारणों की युक्तियुक्तता के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय ग्रंतिम होगा।

(3) पदोन्नित द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो उस संवर्ग में रही हो जिससे उनकी पदोन्नित की गयी।

#### भाग सात-वेतन इत्यादि

22--(1) सेवा में पदों पर चाहे मौलिक या स्थानापन्न रूप में हो या अस्थायी आधार पर, नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।

वेतनमान

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान 1200-30-1560-द0 रो6-40-2046 रुपया है। परिविक्षा ग्रवधि में वेतन

23--(1) फण्डामेन्टल रूल में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी परिवीआधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतन-वृद्धि तभी दी जायगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो और द्वितीय वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायगी जब उसने परिवीक्षा ग्रवधि पूरी कर ली हो। विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो ग्रीर, जहां विहित हो, प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो ग्रीर उसे स्थायी भी कर दिया गया हो :

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा ग्रविध बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना बेतनवृद्धि के लिये नहीं की जायगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे।

(2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के ग्रधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत फण्डामेन्टल रूल्स द्वारा विनियमित होगा :

परन्तु यदि सतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेत-बुद्धि के लिये नहीं की जायगी जब तह कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे।

(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

दक्षता रोक पार करने का मान-दण्ड

10

24--किसी व्यक्ति को--

- (एक) प्रथम दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायगी जबतक कि उसने नियमों का सतोषजनक ज्ञान अजित न कर लिया हो पर्याप्त दौरा और निरीक्षण कार्य न किया हो, विकास कार्य में संतोषज्ञक प्रगति न की हो, उसने पंचायतों पर संतोषजनक नियत्रण न बनाये रखा हो, ग्रौर उसका ग्राचरण सतोषजनक न पाया जाय और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय।
- (दो) द्वितीय दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायगी जब तक कि उसने ग्राम्य विकास कार्यो ग्रौर कार्यक्रमों में निश्चित योगदान ने किया हो, उसका कार्य भौर माचरण संतोषजनक न पाया जाय भौर जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय।

#### भाग ग्राठ-ग्रन्य उपस्नध

पक्ष समर्थन

25--सेवा में पदों पर लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी अन्य सिफा-रिश पर चाहे लिखित हो या मौखिक विचार नहीं किया जायगा। अभ्यर्थी की ग्रोर से अपनी अभ्यिषता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अनहं कर देगा।

ग्रन्य विषयों का विनियमन

26--ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न ग्राते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के दार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों ग्रीर ग्रादेशों द्वारा नियंत्रित होंगें।

सेवा की शतों में शिथिलता

27--जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त किसी व्यक्ति की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विकिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहां वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा, उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शतों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामले में न्याय संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है:

परन्तु जहां कोई नियम ग्रायोग के परामर्श से बनाया गया हो, तो उस नियम की अपेक्षाओं को शिथिल करने या अभिमुक्त करने से पूर्व भ्रायोग से परामर्श किया जायेगा।

व्यावृत्ति

28--इस नियम।वली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे ग्रारक्षण और श्रन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी कि गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और व्यक्तियों की अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्याष्ट्रयों के लिये उपबन्ध किया जाना ग्रपेक्षित हो।

ग्राज्ञा से, कमल कान्त जैसवाल, सचिव ।

IN persuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Go vernor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 6022/XXXIII-1-68-77, dated No vember 18, 1989:

#### No. 6022/XXXIII-1-68-77

#### Dated Lucknow, November 18, 1989

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following, rules regulating recruitment and conditions of service of person sappointed to the Uttar Pradesh Assistant Development Officers (Panchayat-cum-Social Education)

THE UTTAR PRADESH ASSISTANT DEVELOPMENT OFFICERS (PANCHAYAT-CUM-SOCIAL EDUCATION) SERVICES RULE 3, 1989

#### PART I - GENERAL

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Assistant Development Officers (Panchayat-cum-Social Education) Service Rules, 1989.

Short title and commencement

- (2) They shall come into force atonce.
- 2. The Uttar Pra esh Assistant Development Officers (Panchayat-cum-Social Education) service is a non-gazetted service comprising Group 'C' posts.

Status of the

3. In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context: ...

Definitions

- (a) 'appointing Authority' means Joint Director or the Deputy direct r (Administration), as the case may be, looking after the work of administration for the time being, Deputy Director (Administration) Panchayat Raj, Uttar Pradesh:
- (b) 'Citizen of India' means a person who is or is named to be a citizen of India under Part II of the Constitution;
  - (c) 'Commission' means the Uttar Pradesh Public Service Commission;
  - (d) 'Constitution' means the Constitution of India;
  - (e) 'Government' means the State Government of Uttar Pradesh;
  - (f) 'Go ver nor' means the Go ver nor of Uttar Pradesh;
- (g) 'Member of the service' means a person substantively appointed under these rules or the rules or orders in force prior to the commencement of these rules to a post in the cadre of the service;
- (h) 'Service' means the Uttar Pradesh Assistant Development Officers (Panchayat-cum-Social Education) Service;
- (i) 'Substantive appointments' means an appointment not being an ad hoc appointment, on a post in the cadre of the service, made after selection in accordance with the rules and if there are no rules in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instruction, issued by the Governor;
- (i) 'Year of recruitment' means the period of twelfth months commencing from the first day of July of a calendar year.

#### PART II CADRE

4. (1) The strength of the service shall be such as may be determined by Cadre of service the Governor from time to time.

(2) The strength of the service shall, until orders varying the same are passed under sub-rule (1) be; provided that (i) the appointing authority may leave unfilled or the Governor may hold in a beyance any vacant post without there by entitling any person to compensation; and (ii) the Governor may create such additional permanent of temporary posts from time to time as he may consider proper.

#### PART III. RECRUITMENT

"Recruitment" to the service shall as for as possible be made from Source of Rethe following sources:

cruitment

- (i) fifty percent of the total vacancies by promotion from amongst Gram Panchayat Adhikaries;
  - (ii) fifty percent by direct recruitment.

Reservation

6. Reservation for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories—shall be in accordance with the orders of the Government inforce at the time of the recruitments.

#### PART IV QUALIFICATIONS

Nationality

- 7. A candidate for direct recruitment to the service must be:
  - (a) a citizen of India; or
  - (b) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India; or
- (c) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Srilanka or any of the East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tangania (formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently setting in India:

Provided that a candidate belonging to category (b) or (c) above must be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the State Government:

Provided further that a candidate belonging to category (b) will also be required to obtain a certificate of eligibility granted by the Deputy Inspector General of Police, Intelligence Branch, Uttar Pradesh:

Provided also that if a candidate belongs to category (c) above, no certificate of eligibility will be issued for a period of more than one year and the retention of such a candidate in service beyond the period of one year, shall be subject to his acquiring Indian Citizenship.

Note: A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refused, may be admitted to an examination or intervew and he may also be provisionally appointed subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his favour.

Academic qualifications

8. A candidate for direct recruitment to the service must possess at least a Bachelors degree from a University established by law of India.

Preferential qualification

- 9. A candidate who has-
  - (a) served in the territorial Army for a minimum period of two years
    - (b) obtained a 'B' certificate of National Cadet Corps.

Age A

10. A cancidate shall other thing being equal be given preference in the matter of direct recruitment must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of more than 30 years on July 1 the year of recruitment.

Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other categories as may be notified by the Government from time to time shall be greater by such number of years as may be specified.

Character

- 11. The character of a candidate for direct recruitment to a post in the service must be such as to render him suitable in all respects for employment in Government service. The appointing authority shall satisfy itself on this point.
- Note: Persons dismissed by the Union Government or by a State Government or by a Local Authority or by a Corporation of Body owned or controlled by the Union Government or a State Government, shall be ineligible for appointment to any post in the service. Persons convicted of an offence involving moral turpitude shall also be ineligible.

Marital Status

12. A male candidate who has more than one wife living or a female candidate who has married a man already having a wife living, shall not be cligible for appointment to a post in the service:

Provided that the Governor may, if satisfied that there exist special grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

13. No candidate shall be appointed to a post in the service unless he be Physical Fitness igood mental and bodily health and free from any physical defect likely to efficient performance of his duties. Before a candidate is finally approved for appointment he shall be required to produce a Medical Cer ificate of fitness in accordance with the rules framed under Fundamental rule-10 and contained in Chapter III of the Financial Hand Book, Volume II,

Provided that a medical certificate of fitness shall not be required from a candidate recruited by promotion.

#### PART V - PROCEDURE FOR RECRUITMENT

14. The appointing authority shell-determine and intimate to the Commission, the number of vacancies to be filled during the course of the year as also the number of vacancies to be reserved for cancidates belonging to the Schedule castes, Scheduled Tribes and other categories under Rule 6.

Determination of

15. (1) Direct recruitment to the service shall be made through the Commission on the basis of a competitive examination.

Procedure for direct recruitment

- (2) Application for permissions to appear at the competitive examination shall be called by the commission in the format advertised by them prescribed form which may be obtained from the Secretary to the Commission on payment
- (3) No candidate shall be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission granted by the Commission.
- (4) After the results of the written examination have been received and tabulated the Commission shall, having regard to the need for securing due representation of the candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and others under rule-6 call for interview such numbers of candidates as on the result of the written examination have come up to the standard fixed by the Commission in this respect. The marks awarded to each candidate at the interview shall be added to the marks obtained by him in the written examina tion.
- (5) The Commission shall prepare a list of the candidates in order of their proficiency as disclosed by the aggregate of marks obtained by each candidate at the written examination and interview and recommend such number of candidates as they consider fit for appointment. If two or more candidates obtain equal marks in the aggregate the name of the candidate obtaining higher marks in the written examination shall be placed higher in the list. The number of names in the list shall be larger but not larger by more than 25 per cent than the number of the vacancies. The commission shall forward the list to the appointing authority.
- NOTE :- Direct recruitment to the post in the service may be made on the result of combined Lower Subordinate Services Examination (Graduate
- 16. Recruitment by premotion shall be made on the basis of seniority subject to the rejection of the unfit in accordance with the Uttar Pradesh Promotion by Selection in Consultation with Public Service Commission (Procedure) Rules, 1970 as amended from time to time.

Promotion for recruitment promotion

17. If in any year of recruitment appointment are to be made both by direct recruitment and by promotion, a combined select list shall be prepared by taking the names of candidate from the relevant lists alternately, the first ame in the list being of the person appointed by promotion.

Combined select

#### PART VI - APPOINTMENT, PROBATION, CONFIRMATION AND SENIORITY

18. (1) Subject to the provision of Sub-rule (2) the appointing authority shall make appointment by taking the name of the candidates in the order in which they stand in the lists prepared under rules-15, 16 or 17 as the case may be;

Appointment

(2) Where in any year of recruitment, appointments are to be made both by direct recruitment and by promotion, regular appointments shall not be made unless selections are made from both the sources and a combined list is prepared in accordance with rule-17;

- (3) If more than one orders of appointment are issued in respect of any one selection, a combined order shallalso be issued, mentioning the name of the person in order of seniority as determined in the selection or, as the case may be, as it stood in the cadre from which they are promoted. If the appointment are made both by direct recruitment and by promotion names shall be arranged in accordance with the cyclic order referred to in Rule-17;
- (4) The appointing authority may make appointments in temporary or officiating capacity also from the lists referred to in sub-rule (1). If no candidate borne on these lists is available, he may make appointment in such vacancies from amongst persons eligible for appointment under these rules. Such appointments shall not last for a period exceeding one year or beyond the next selection under these rules, whichever be earlier and where the post is within the purview of the Commission, the provisions of regulation 5(a) of the U. P. Public Service Commission (Limitation of Functions) Regulation, 1954 shall apply.

Probatio

- 19. (1) A person on appointment to a post in the service in or against a permanent vacancy shall be placed on probation for a period of two years.
- (2) The appointing authority may, for reasons to be recorded in writing, extend the period of probation in individual cases specifying the date upto which the extention is granted. Provided that save in exceptional circumstances the period of probation shall not be extended beyond one year, and in no circumstances, beyond two years.
- (3) If it appeals to the appointing authority at anytime during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, he may be reverted to his substantive post, if any, and if he does not hold a lien on any post, his services may be dispensed with.
- (4) A probationer who is reverted or whose services are dispensed with under sub-rule (3) shall not be entitled to any compensation.
- (5) The appointing authority may allow continuous service, rendered in an officiating or temporary capacity in a post included in the cadre or any other equivalent or higher post, to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.

Confirmation

- 20. A probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or the extended period of probation if :-
  - (a) he has passed the prescribed departmental examination, if any,
  - (b) he has successfully undergone the prescribed training, if any;
  - (c) his work and conduct are reported to be satisfactory;
  - (d) his integrity is certified; and
  - (e) the appointing authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmation.

Seniority

21. (1) Except as hereinafter provided the seniority shall determined from the date of the order of substantive appointment and two or more persons are appointed together, by the order in which their names are arranged in the appointment order.

Provided that if the appointment order specifies a particular back date with offect from which a person is substantively appointed that date will be deemed to be the date of substantive appointment and in other cases, it will mean the date of issue of the order.

Provided further that if more than one orders of appointment are issued in respect of any one selection, the seniority shall be as mentioned in the combined order of appointment issued under sub-rule (3) of rule-18:

(2) The seniority interse of the persons appointed directly on the result of any one selection shall be the same as determined by the Commission:

Provided that a candidate recruited directly may loose his seniority if he fails to join without valid reasons when vacancy is offered to him, the decision of the appointing authority as to validity of reasons shall be final.

3) The seniority interse of persons appointed by promotion shall be the same as it was in the cadre from which they were promoted.

#### PART VII-PAY ETC.

22. (1) She scale of pay admissible to persons appointed to the posts in the service whether in a substantive or officiating, capacity or as a temporary measure, shall be such as may be determined by the Government form time to time.

Scale of Pay

- (2) The scale of pay at the time of the commencement of these rules is Rs. 1200—30—1560—E.B.—40—2040.
- 23. (1) Notwithstanding any provision in the Fundamental Rules to the contrary, a person on probation, if he is not already in permanent Government service, shall he allowed his first increment in the time scale when he has completed one year of satisfactory service and second increment after two years privice when he has completed the probationery period has passed departmental examination and undergone training where prescribed and is also confirmed:

Pay during probation

Provided that if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction such extention shall not count for increments unless the appointing authority directs otherwise.

- (2) The pay during probation of a person who was already holding a post under the Government shall be regulated by the relevant fundamental rules. Provided that, if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.
- (3) The pay during probation of a person already in permanent Government service shall be regulated by the relevant rules, applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State.
  - 24. No person shall be allowed to cross :-

Criterion for crossing efficiency

- (i) the first efficiency bar unless it is found that he has acquired satisfactory knowledge of rules, does sufficient touring and inspection work, has made satisfactory progress in development work, has maintained satisfactory control over the Panchayats and his work and conduct are found to be satisfactory and unless his integrity is certified;
- (ii) the second efficiency bar unless he is found to have made a definite contribution to village development works and programmes and his work and conduct are found to be satisfactory and unless his integrity is certified.

#### PART VIII—OTHER PROVISIONS

25. No recommendationts either written or oral, other than those required under the rules applicable to the post in the service, will be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature will disqualify him for appointment.

Canvassing

26. In regard to the matters not specifically covered by these rules or by special orders, persons appointed to the service shall be governed by the rules, regulations and orders applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State.

Regulation of other matters

27. Where the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of service of persons appointed to the service causes undue hardship in any particular case, it may, notwithstanding anything contained in the rules applicable to the case, by order, despense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner:

Relaxation in conditions of service

Provided that where a rule has been framed in consultation with the Commission, that body shall be consulted before the requirements of that rule are relaxed or dispensed with.

Saving

28. Nothing in these rules shell affect reservations and other concessions, required to be provided for the candidate belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders of the Government issued from time to time in this regard.

By order,
KAMAL KANT JAISWAL,
Sachiv.

्र अस्तर प्रदेश सरकार पंजानकी, राज्ञ अनुभागना तंष्या: १९७७ . . /33-1-94-116 92

्तियान के शनुहुछेद ३०१ के परन्तुक दीरा प्रदत्त शिक्ति का पुनीय करके टाज्यपाल उत्तार प्रदेश तहा पक स्थितारा अधिकारी विचाचत इवं समाज गतिला ६ सेवार तियमा वली , १९८० को संगो पिट करने ही. द बिट भी नियमार्गित्वा नियमाद्यली वनारोगी उत्तर प्रदेश तथायम विकृति अधिक्षिति । अधिकारी तथा के विकार अधिक संसोधन्। देखाः वनिधेनाचारोः, १००५% विकास

1 का 1 क्षेत्रक विकास स्टाही के इत्यर के प्रदेश सहायक क्षिका ते के पिका रोट स्वीम स्ट ं इन त्याप्त जिल्लाहर्षाः पृथम् संगोपनः तेता जिल्लान्यक्ति । १९६५ वर्षे Transition Public

121 क पुरन्त प्रश्ति शोगी पहर

2. अनुसार प्रवासिक्त विकास विकास अधिकारो अस्मार स्थान विकास क्षेत्री विवास इसी विश्वित हैं है कि कि लिहें हैं है। उससे किस मासती है है। 和中心,相对 对形型门等通过为外边界的证据不可能形式 भीताल गणा भीतावस रहा भीताले हिल्ली हैं लिए हैं हैं हैं हैं

777777-1

शंबपा स्ती पोची जिते राज्यनाल दोरा साध-तमध मंद अवमारिक किया बाची १२ : जब तक चींद्र-प्रमु नियम् : u अने वेशकारित्र वहारी, महिन् करांचे तेया की संस्था संस्था 984 612W:

..... े अपनेत् स्तार्थः <u>च्यान्य</u>्यात् विवस्त ्य-१। होवा की तिवस्य कार्यक्षिक्षित्र होता की तवस्य तथा स्ती होगी ४ . जिली राज्यपाल द्वारा तम् तम्य पर अवयारितः चीः जान

12 श ज्याति । कि उपनिष्ट ।।। के अपीन विश्वितीन भरते के आहार न दिवे नावें. -क्षील दर्भ है। विविधान विधान तेवा की तरम तेवाने उसी होगी जिसह ्याचित्री गर्डे हे 🗁

राज्याताल जो आस्थातिस स्व क्षाती है - जिल्ली कोई स्विन्ति । न होगा, קיומור הי ניימור ה פייחוד, इती र शास्त्रमान भेते । विस्थानको पार्थी पार सूचन पार जिल्ही यह उनेका हत्यी । अभिनित्ता स्थाने जे क्षा व कार्य यह उचित

क्षा अभूतित प्राधिकारी क्या किया पट को निवना अट हुए छोड़ तल्या है पा भी हुए होंड़ तालों है या प्राच्यामा उत्ते आस्थानत त्व तहते हैं, जिलों को है। व्यक्ति प्रतिकर का स्वतार

्राधीक्ष साजवणात हेते इतिहासिक स्थापी चन् अत्याची पति जा दूरत कर हती है

हाल रेक्ट्रांट के, तीने लाइकी में तीन का पहला है। हर्मकार के विवास समा हिन्दा रूप रिवार जावार, उपनेति :-

1 0 1 1 mm and and a med from

्र स्वांतान नेत्राच <u>ार प्रतित्त ५० लिया अं भती, प्रतार</u> त्तान्यं, निम्नतिर्गित शीलीं

त की जामगी-क्षा हुल हिल्लामी जा मनायं प्रतिस्था महार मामा अधिकारियों में से पटोन्सी।

rate grant premit and 2 16 1/2 IN 1 6-1. 1

WHEN THE PROPERTY OF THE PARTY 5- तेया में किली पर पर भारी, मोक्तिय ्या ते निवुषत ग्राम वंचान्य जिल्हानि भे ते, पदोन्ति शास की जागी।

इत्तर क्षिप्रमाधनी कर किला १५ किलान दिया जनपंगा

उत्तर विवासक्ति है, बाद स्वामान में वृक्ष्य भवे किया १८ है त्यान पर, स्ताम=२ में दिया गथा विधा पर विधा भागमा. जवांच :--

### 5:11.12:1-1 वित्तिमान कियाग

16- पतान्ति द्वारा भति अनुवयुक्त को अन्दोन्सार हरेंगे तुप विवेष्ठवता वे जापार पर लग्द-तम्ब पर घथा तेशीनियत अस्तर प्रेम लोज तेवा आयोज सवराक्षी वयनी निति छान्या र्गस्याच्योर, १९७० वे अनुसार क्षी कायती ।

## ध्याद द्वारा प्रतिस्थापित निधमः

16-11 व पदो न्निति द्वारा भती, अनुप्रमुखा को अस्पीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आपार पर, उत्तर पृदेश विभागीच पटो नातिसमिति का गठन शोबा आयोग वे क्षेत्र के घाडर है न्हीं के लिए हिल्ला मार्ग 1992 के अपूर्वार गाँउत भे नाने जेतते भटन तांगात ह बाध्यम ते जो जायते । 123 निवृध्यि प्राधिनाते अस्तिनं क नजा हो ज होना जा होता लोज तेवा आयोग है जिसे मोहर में मो ण्यः वयनो नति जनता नृति कार्याणने, 1986के अमुसार सेरान गरेना और उने उनकी टरिन गंकियों और उन्हें सेनिया के अन अंभियों वे साथ, जो जीया करे जी. द्वा तीती है हम हेरा । १३ १ वस्त वाध्योत अस्तित्व १०: भे निर्देश्य . अभिनेतों हे आपार पर इन्यपियों हे लालों पर विधार छोगी और पवि यह जायान ताक्षे तो अन्यर्थियों का ताकात्वार भी वर तन्ती है। १५३ कान समिति वयन किये को अध्यक्ति की विभावता हुए हैं। देश वेन तंत्र हैं हो.

चित्रते उन्हों वदो न्यांत को वानी है, एक सूची तथार करेगी और उते निवृद्धित प्राधिकारी को अंग्रतारित करेगी ।

उच्या निवमायली का नियम 17 निकास दिया जायमां । -

आचा ते,

ចាច ជំនាក់ ។ជំនំ, តាមែរ !

<u> 17 WT</u>